

1935 का भारत शासन अधिनियम

(B.A. SEMESTER-VI) Paper XIII (13) (Guess Q-9)

1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि

1932 ई० के सविनय अवज्ञा राष्ट्रीय आंदोलन को यद्यपि अंग्रेजी सरकार पत्र का सहारा लेकर कुचलने में सफल हो गई थी किंतु उसे यह अहसास हो गया कि पत्र की नीति के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को अधिष्ठानों तक पंढाया नहीं जा सकता है। अब सरकार भविष्य में ऐसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन को संभालना को समर्थ करने के प्रयास पर विचार करने लगी। उसने कांग्रेस को विभक्त करने की योजना बनाई। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने 1935 ई० का 'भारत शासन अधिनियम' प्रस्तुत किया। क्योंकि कि उसे उम्मीद थी कि संवैधानिक सुधारों के इस अधिनियम से कांग्रेस के सदस्यों को संतुष्ट एवं औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित कर लिया जायेगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन की सभी दुर्गन्धों को पत्र से समाप्त कर दिया जायेगा। अपनी इन्हीं नीतियों को अमली जामा - पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' पारित किया।

भारत सरकार अधिनियम - 1935 के पारित होने से पूर्व उसके 'सारजन आयोग रिपोर्ट', नेहरू समिति की रिपोर्ट, विधान में संपन्न तीन गोलमेठ सम्मेलनों में इसे कुछ विचार-विमर्शों से सहपता ली गई। तीसरे गोलमेठ सम्मेलन के संपन्न होने के बाद कुछ प्रभाव 'श्वेत-पत्र' नाम से प्रकाशित इसे, जिनपर ७ दस के लिए विधान के दोनों सदन एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अन्ततः इस

रिपोर्ट के आधार पर '1935 का अधिनियम पारित हुआ। 1935 का अधिनियम काफी लंबा एवं जटिल था। इसे 3 जुलाई, 1936 को अंग्रेजों से लागू किया गया, किंतु पूर्णरूप से युवाओं के वार अक्टू, 1937 ई. में यह लागू हो पाया।

1935 ई. के अधिनियम की विशेषताएँ

1935 के अधिनियम में कुल 321 धाराएँ एवं 10 सूचियों का समावेश था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:—

1. केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर-जनरल कुछ पाषाणों की सहायता से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल व मंत्रियों से सौंपा गया। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे।

2. इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में दो सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।

3. इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में महाधिकाय का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और अधिक बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया।

4. इस अधिनियम में एक 'अखिल भारतीय संघ' की व्यवस्था की गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों

चाहूँ कमिश्नर, प्रांतों व देशी रियासतों से मिलकर होता था, किंतु यह व्यवस्था लागू न हो सकी, क्योंकि प्रस्तावित संघ में भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना स्वीकार्य पर निर्भर करता था।

5. प्रांतों में भेद्य शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई।
6. कर्मा (वर्तमान में म्यांमार) को भारत से पृथक् कर दिया गया।
7. विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम-न्यायालय रही था। अंतिम न्यायालय 'प्रिवी काउंसिल' नहीं।

8. इस अधिनियम के द्वारा गृह-संसार में महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके विभिन्न विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता था, उसपर उन्होंने भारतभंगी के अधिकार को समाप्त कर दिया और साथ ही 'भारतीय परिषद्' को समाप्त कर दिया गया।

9. 1935 के अधिनियम के तहत, एक संघीय न्यायालय एवं सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।

1935 के अधिनियम का मूल्यांकन

पं. जवाहरलाल ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि, 'यह अधिनियम दासता का धीषणा पत्र है'।

वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बड़े-बड़े अंग्रेजों के हाथों से सीमित रखी थी। इसके प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनायी गई थी किसे भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाये।

इस अधिनियम को बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने कहा कि
न तो यह हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज ।

इससे पूर्व यह बात स्पष्ट हो गई थी कि संप्रियायित्वात्मक चुनाव
प्रणाली भारत के लिए अहितकर है और सभी राजनैतिक दलों ने इसे
एक सिरे से नकार भी दिया था, फिर भी इस अधिनियम के द्वारा
न केवल इसे बना रते दिया गया बल्कि इसका विस्तार भी किया
गया । इस अधिनियम से नये संविधान के स्विकार होने या
भारतीयों द्वारा अपने मध्य के निर्माण करने का कोई प्रबंध नहीं था ।
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत
की आज़ो की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी ।

1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद
या भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई कमी नहीं की गई ।
भाष्य में सब प्रावधानों को देखते इसे सहृदी न ही
कहा था कि, " भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत के
अविष्य की राजनीति प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है ।"

Rajesh K. Singh,

Asst. Prof. (History)

D. S. P. M. U.,